

प्रेषक,

जे०पी०जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक ५ अप्रैल, 2011

विषय:-वित्तीय वर्ष 2011-12 में नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु प्रावधानित धनराशि निर्गत करने के सम्बंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र रांख्या-रोजी-59/होगा०/2010/44 दिनांक 08-04-2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के रांध में श.जनादेश सं०-२६१/XX(5)10-07(नांसु0) / 11 दिनांक 07-04-2011 के अनुक्रम में मुझे आपसे रह करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011-12 में नागरिक सुरक्षा विभाग के लोन फ्रिरणानुसार रु० 4.79,000/- (रूपये चार लाख, उन्नयासी हजार मात्र) धनराशि की सहाय स्वीकृति तो प्राप्त करने के लिए अप्रैल अंतिमिति शर्ती के अधीन प्रदान करते हैं।

03-स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

0301 सामान्य

मानक मदधनराशि (हजार रु० में)

1	04- यात्रा व्यय	19
2	08-कार्यालय व्यय	25
3	11-लेखन सामग्री और फार्गो जी छपाई	12
4	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25
5	13-टेलीफोन व्यय	20
6	15-गाडियों का अनुरक्षण और एट्रोल आदि जी खरेट	45
7	17-किराया उपशुल्क और कर- खामित्व	200
8	26-मशीन और सज्जा/उपकरण संयन्त्र	25
9	31-सामग्री सम्पूर्ति	1
10	42-अन्य व्यय	5
11	44-प्रशिक्षण व्यय	25
12	45-अवकाश यात्रा व्यय	12
13	46-कम्प्यूटर क्रय	50
14	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	15
	योग:- (रूपये चार लाख, उन्नयासी हजार मात्र)	<u>479</u>

2— जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हो तो पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थार्थी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम आधिकारी द्वारा स्टैम्पेटों की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3— बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में भी तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग या अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याजा में कोई आधार/वायित्व सुनिश्चित किया जाय।

4— जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का दिवरण नेटरिंग प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से किस विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह दिलम्बतम 20 तारीख तक उपलब्ध करा गा सुनिश्चित किया जाय।

5— मितव्यिता सम्बंधी शासन द्वारा समय-समय पर जरी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6— इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-रिविल रक्षा-03-रथापना (25 प्रतिशत के द्वारा पोषित)-00-आयोजनेत्तर की सुरांगत इकाइयों के नामे हाला राखेगा।

7— यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 के काग में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जे०पी०जो०ी)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 308/xx(05)/10-07(हो०गा०)/ 10 तददिनां ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं उव्यश्यक का जाही रहते प्रेषितः—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय भोर्ता विलेंग, मजर रहरादून।

2—निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन,

3—वित्त अनुभाग-1/5

4—एन० आई० सी० सचिवालय परिसर।

5—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम०रस०व०हा०)
अनु सचिव।